आर.एन.आई. पंजीयन क्र. 39596/82 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)

साप्ताहिक

मालव आँचल

वर्ष 47 अंक 28 (प्रति रविवार) इंदौर, 31 मार्च से 06 अप्रैल 2024 पृष्ठ-8 मूल्य 3 रुपये

मोदी की विरोधियों को चुनौती, भ्रष्टाचारी कितना ही बड़ा क्यों न हो, एक्शन जरूर होगा जिसने लूटा है, उसे लौटाना होगा

यह चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट-योगी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मेरठ में जनसभा कर चुनावी शंखनाद कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरठ की धरती क्रांति और क्रांतिवीरों की धरती है। इस धरती ने चौधरी चरण सिंह जैसे महान सपूत देश को दिए हैं। हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला है। मैं चौधरी साहब को आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा इस धरती से अलग ही रिश्ता है। 2014 और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ की इस पावन भूमि से की थी।

अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। 2024 का चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने के चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने, इसका चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। 2024 का यह जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था तब देश में गरीबी थी, जब देश पांचवें नंबर पर पहुंचा, तब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए। अब सोचिए जब भारत दुनिया में नंबर तीन पर पहुंचेगा, तब देश में गरीबी दूर होगी ही, साथ ही एक सशक्त मध्यमवर्ग देश को नई ऊर्जा देने वाला होगा। मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा आपके सामने हमारा 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में सेना के लिए वन रैंक वन पेंशन को लेकर पहले कई वादे हुए, देश में ये लागू होगा, इसकी आशा हमारे जवानों ने छोड़ दी थी, लेकिन हमारी सरकार ने इस लागू किया। तीन तलाक के खिलाफ आज न सिर्फ कानून बन गया है, न कि ये हजारों मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी बचा रहा है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण भी पहले असंभव लगता था, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज सच्चाई बन चुका है। पीएम मोदी ने अपने बड़े फैसलों का ज़िक्र कर कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 कभी हटेगा, ये भी लोगों को असंभव लगता था, लेकिन हमारी सरकार ने हटा दिया।

इसके हटने के बाद जम्मू कश्मीर का तेज विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं गरीबी से तपकर यहां पहुंचा है। इसकारण हर गरीब का दुख और पीड़ा, तकलीफ मैं भलीभांति समझता हूं। हमारी सरकार ने गरीबों के लिए योजनाएं बनाई। गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की आयुष्मान योजना बनाई, हमारी सरकार 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। जिस गरीब को किसी ने नहीं पूछा, उस गरीब को मोदी ने पूजा है।

राष्ट्रपति ने आडवाणी को घर जाकर भारत रत्न दिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को आज देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उनके घर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया कि आडवाणी के खराब स्वास्थ्य के कारण ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 फरवरी को उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की थी। वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नाना जी देशमुख के बाद ये सम्मान पाने वाले भाजपा और आरएसएससे जुड़े तीसरे नेता हैं।

नरसिम्हा राव समेत 4 शख्सियतों को मरणोपरांत भारत रत्न- राष्ट्रपति ने शनिवार (30 मार्च) को राष्ट्रपति भवन में 4 शख्सियतों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉ. एमएस स्वामीनाथन शामिल हैं।

दक्षिण भारत पहुंचाएगा भाजपा को 370 के आंकड़े के पार-गडकरी

नागपुर (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 370 सीट का लक्ष्य हासिल करने को लेकर पूरा भरोसा जताकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी की मौजूदा 288 सीट में अतिरिक्त सीट दक्षिण भारत से जुड़ेंगी। एक साक्षात्कार में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि उनके मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) 400 सीट के आंकड़े को पार करेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए ठोस कार्यों के कारण मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं। उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि मोदी सरकार विपक्ष को कमजोर करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रतिद्वंद्वियों को लोगों का विश्वास जीतकर विपरीत परिस्थितियों से उबरने का प्रयास करना चाहिए।गडकरी ने कहा, क्या विपक्ष को कमजोर या मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है? जब हमारे पास सिर्फ दो सांसद थे और हम कमजोर थे, तब हमें सहानुभूति के तौर पर कभी कोई पैकेज नहीं मिला। गडकरी ने नागपुर में बड़े रोड शो के द्वारा अपना प्रचार अभियान शुरू किया।

आयकर नोटिस मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत

लोकसभा चुनाव तक नहीं होगी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज सोमवार को आयकर विभाग ने भरोसा दिलाया कि लोकसभा चुनाव का समय होने के चलते इन पैसों की रिकवरी को लेकर विभाग कोई करवाई नहीं करेगा। इसी के साथ आयकर विभाग के नोटिस मामले में कांग्रेस को कुछ दिनों के लिए राहत मिलती नजर आई है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने भरोसा दिलाते हुए कहा है कि अभी चूंकि लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, लिहाजा हम इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई करवाई नहीं करेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने इस मामले में सोमवार सुनवाई की। आयकर विभाग की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी। अब इस मामले की सुनवाई अदालत 24 जुलाई को करेगी। आईटी की ओर से तुषार मेहता ने अदालत में कहा, कि हमनें 1700 करोड़ का नोटिस भेजा है, लेकिन लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने इसी के साथ ही

मामले की सुनवाई जून महीने में करने की बात कहते हुए कहा कि तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा, कि क्या आपने जो डिमांड रखी है, उसे स्थगित कर रहे हैं? इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा, कि नहीं हम बस ये कह रहे है की हम चुनाव तक कोई कार्रवाई नही करेंगे। आयकर विभाग ने स्पष्ट कहा कि इस मामले की सुनवाई जून के दूसरे हफ्ते में की जाए। फिर मांग चाहे 1700 करोड़ हो या 3500 करोड़, यह मामला यहां इस केस में लंबित नहीं हैं। सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा दिलाया कि हमारा बयान रिकॉर्ड किया जाए या नहीं, हम चुनाव खत्म होने तक कांग्रेस के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे। जहां तक मामले की बात है तो यहां बतलाते चलें कि लोकसभा चुनाव के ऐन पहले कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग ने एक नया नोटिस जारी किया, जिसके जरिये आंकलन वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लिए 1,745 करोड़ रुपये के कर की मांग की गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार आयकर विभाग ने अभी तक कांग्रेस से कुल 3,567 करोड़ रुपये के कर की मांग कर चुका है। ताजा नोटिस 2014-15 (663 करोड़ रुपये), 2015-16 (करीब 664 करोड़ रुपये) और 2016-17 (करीब 417 करोड़ रुपये) से संबंधित बताया गया है।

सूत्रों की मानें तो आयकर अधिकारियों ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली कर छूट समाप्त कर दी है और पार्टी पर कर लगाकर नोटिस थमा दिए हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस ने शुक्रवार को ही कहा था कि उसे आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है, जिसमें करीब 1,823 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है। इनकम टैक्स अधिकारियों ने पिछले वर्षों से संबंधित कर मांग के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपये पहले ही निकाल लिए हैं।

संपादकीय

लोकतंत्र की रक्षा की दिशा में एक और पहल

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए देश के सभी राजनीतिक दलों को यह आदेश दिया है कि जिस प्रत्याशी को भी वह संसद के लिए अपना उम्मीदवार बना रहे हैं उसका सारा आपराधिक रिकार्ड, अगर वह अपराधी है, तो चुनाव आयोग को भेजा जाए और साथ ही यह सारी जानकारी सोशल मीडिया तथा समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को दी जाए। यह भी कहा गया है कि यह कारण बताया जाए कि आखिर आपराधिक छवि वाले को टिकट क्यों दिया गया। इस आदेश को लागू करने का सारी जिम्मेवारी चुनाव आयोग को सौंपी गई है और यह भी कहा गया है कि इस आदेश का अगर पालन नहीं किया गया तो राजनीतिक पार्टियों पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन का केस बनाया जाएगा। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का सख्ती से अनुपालन कराएगा, जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार को अपने विरुद्ध आपराधिक मामलों को अपने शपथपत्र के अतिरिक्त अखबारों एवं न्यूज चैनल के माध्यम से मतदाताओं को अवगत कराने की बात कही गई है। इसके लिए निर्धारित समय सीमा का भी सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। इसे लेकर आयोग द्वारा सभी निर्वाची पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक उम्मीदवार को उनके खिलाफ आपराधिक मामले (चाहे वे लंबित मामले हों या पूर्व के मामले हों जिनमें वे दोषी ठहराए गए हों) की जानकारी तीन बार अखबारों तथा चैनल के माध्यम से देनी होगी। राजनीतिक दलों को भी अपने उम्मीदवारों के लिए इसका अनुपालन करना होगा। आयोग ने इसका प्रारुप और फान्ट भी तय कर दिया है। आपराधिक मामलों की जानकारी तीन निर्धारित अवसरों पर देनी होगी, ताकि मतदाताओं को जानने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। उम्मीदवारों को ऐसे मामले की जानकारी नामांकन दाखिल की तिथि के पहले चार दिनों के भीतर, इसके बाद अगले 5वें से 8वें दिनों के बीच तथा अभियान के नौवें दिन से अंतिम दिन तक (मतदान की तिथि से दो दिन पहले तक) न्यूनतम 12 फ़ान्ट आकार में उपयुक्त स्थान पर प्रकाशित करानी होगी। उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों द्वारा इसका अनुपालन नहीं करने पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने इसकी रिपोर्टिंग के लिए भी प्रारुप सभी निर्वाची पदाधिकारियों को भेज दिया है। सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी अनिवार्य रूप से देनी होगी ताकि मतदाता उनकी वेबसाइट पर भी जाकर जानकारी प्राप्त कर सकें तथा उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों से अवगत हो सकें। चुनावी सुधारों पर होने वाली तमाम चर्चाओं में राजनीति का अपराधीकरण एक अहम मुद्दा रहता है। राजनीति का अपराधीकरण - 'अपराधियों का चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना' - हमारी निर्वाचन व्यवस्था का एक नाजुक अंग बन गया है। हाल ही में जारी आँकड़ों के अनुसार, संसद के 46 प्रतिशत सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं। लोकसभा में 542 सांसदों में से 233 (43त्न) के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। 233 में से 159 (29त्न) पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। ऐसे सांसदों में से सबसे अधिक केरल और बिहार से हैं। केरल के इडुक्की लोकसभा के सांसद कुरियाकोस पर सबसे अधिक 204 केस दर्ज हैं। वहीं, राज्यसभा की 233 में से 71 (31त्न) सांसदों पर आपराधिक केस लंबित हैं। 71 में से 37 सांसदों पर गंभीर अपराध के मामले, 2 पर हत्या, 4 पर हत्या का प्रयास, 3 पर महिलाओं के खिलाफ अपराध, 1 पर दुष्कर्म का मामला दर्ज है। 106 सांसदों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई, ईडी और एनआईए के समक्ष मामले लंबित हैं। सीबीआई के पास 121 पूर्व व वर्तमान सांसदों व विधायकों के मामले लंबित हैं। इनमें से 51 मामले सांसदों से संबंधित हैं। इन 51 में से 37 पूर्व सांसद हैं और 5 की मृत्यु हो चुकी है। एनआईए के पास 4 सांसद व विधायकों के खिलाफ जांच लंबित है। इनमें से 2 सांसद है। ईडी के पास 51 सांसदों के खिलाफ जांच लंबित है।

इंडिया की लोकतंत्र बचाओ महारैली के बेसूरे

ललित गर्ग

दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन इंडिया की लोकतंत्र बचाओं महारैली में जुटे 28 दलों के नेता आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कोई प्रभावी संदेश देने में नाकाम रहे हैं। भले ही चुनाव के ठीक पहले विपक्षी दलों ने इसके जरिए अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने में कामयाबी हासिल की हो। लेकिन यह एकजुटता भ्रष्ट नेताओं को बचाने की एक मुहिम ही बनकर सामने आयी है। इसमें स्पष्ट रूप से केन्द्र सरकार की भ्रष्टाचार पर गई कार्रवाई की बौखलाहट झलक रही थी। इस रैली में सभी दलों के नेताओं ने देश विकास के मुद्दों, सिद्धान्तों एवं नैतिक तकाजे की बजाय मोटे तौर पर सत्ता पक्ष की भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इसी के इर्दगिर्द ही अपनी बातें रखीं। लोकतंत्र बचाओ रैली से उपजे विचारों ने किन्हीं पवित्र उद्देश्यों के बजाय सत्ता हासिल करने की लालसा को ही उजागर किया, यह निराश करने वाली रैली किसी बड़े बदलाव की वाहक बनती हुई नजर नहीं आयी।

इस रैली में भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शानदार जीत की संभावना से बौखलाए नेताओं की खींच ही ज्यादा सामने आयी है। यही कारण है कि रैली में जो मुद्दा जोरशोर से उठा, वह यह रहा कि यदि भाजपा फिर से सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और संविधान भी। यह समझना कठिन है कि कोई दल लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करता है तो उससे लोकतंत्र और संविधान कैसे खत्म हो जाएगा। आम जनता के मतों से जीत हासिल करने वाला दल किस तरह से लोकतंत्र को ध्वस्त करने वाला हो सकता है। विपक्षी एकता का यह महाकुंभ मोदी को कोसने की बजाय किन्हीं ठोस मुद्दों के सहारे कोई प्रभावशाली विमर्श खड़ा करने की कोशिश करता तो वह आम जनता को आकर्षित करता और यही स्वस्थ राजनीतिक परिपक्वता का परिचायक होता। लेकिन ऐसा न होना समूचे देश के विपक्षी दलों की नाकामी, उद्देश्यहीनता एवं राजनीतिक अपरिपक्वता का द्योतक हैं।

इस रैली में अनेक मुद्दे उठे, जिनमें प्रमुख रहा केंद्रीय एजेंसियों का कथित दुरुपयोग और राजनीतिक भ्रष्टाचार। प्रियंका गांधी ने इस रैली में सरकार के सामने पाँच माँगें रखीं। इनमें प्रमुख दो हैं जिनमें चुनाव आयोग से माँग की गई है कि विपक्षी नेताओं पर छापों की कार्रवाई रोकी जाए। दूसरी और महत्वपूर्ण माँग ये है कि गिरफ्तार हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए। इस रिहाई की माँग के पीछे कांग्रेस का उद्देश्य बचे-खुचे संगठनों या पार्टियों को इंडिया गठबंधन से जोड़े रखना है। नीतीश कुमार और ममता बेनर्जी जैसे मज़बूत खम्भे पहले ही उखड़ चुके हैं इसलिए जो कुछ बचा है उसे कांग्रेस समेटे रखना चाहती है, यही उसकी विवशता है। वैसे, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के आपसी अंतर्विरोध की छाया भी इस रैली दिखी। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि विरोध किसी खास व्यक्ति से जुड़ा नहीं बल्कि मौजूदा सरकार की तानाशाही के खिलाफ केंद्रित है। जबकि इस रैली का मकसद आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करना बताया गया। यहां आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस के बीच के अन्तर्विरोध को सहज ही समझा जा सकता है।

यह रैली भले ही अठाइस दलों का जमावड़ा बनी, इसे विपक्षी दलों की एकजुटता का प्रदर्शन भी कहा गया है। लेकिन जबसे इंडिया गठबंधन बना है, तब से उसमें टूट एवं बिखराव के स्वर सुनाई दे रहे हैं। विचारभेद के साथ मनभेद भी सामने आये हैं। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक तमाम राज्यों में टिकट बंटवारे के सवाल पर इंडिया गठबंधन से जुड़े दलों की आपसी खटपट की खबरें भी आ रही थीं। भले ही ये विवाद गिनी-चुनी सीटों को लेकर थे, लेकिन संदेश स्पष्ट था कि चुनाव सिर पर आने के बाद भी इंडिया गठबंधन से जुड़े दल एकजुट नहीं हो पा रहे। रामलीला मैदान की रैली के जरिए इन दलों ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि मोदी विरोध एवं भाजपा को सत्ता से दूर करने के मुद्दों पर वे एक स्वर में बोल सकते हैं और लगातार बोलते भी रहे हैं, फिर उसके लिये इस महारैली की क्या जरूरत? निश्चित ही एकजुटता के ये स्वर बेसूरे, असहज एवं बनावटी है, इंडिया गठबंधन के राजनैतिक क्षितिज पर जो वरिष्ठ राजनेता हैं उनकी आवाज व किरदार भारतीय जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा है। इंडिया गठबंधन से जुड़े दलों की केन्द्र एवं प्रांतों की सरकारों के शासन-काल में तो अपराध, भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिकता के जबड़े फैलाए, आतंकवाद, प्रांतवाद, जातिवाद की जीभ निकाले, मगरमच्छ सब कुछ निगलता रहा है। सब अपनी जातियों और ग्रुपों को मजबूत करते रहे हैं-- देश को नहीं। प्रथम पंक्ति का नेता ही नहीं है जिसे मोदी के मुकाबले में खड़ा किया जा सके। भारत के लोग केवल बुराइयों से लड़ते नहीं रह सकते, वे व्यक्तिगत एवं सामूहिक, निश्चित सकारात्मक लक्ष्य के साथ जीना चाहते हैं। अन्यथा जीवन की सार्थकता नष्ट हो जाएगी।

दो तरह के नेता होते हैं- एक वे जो कुछ करना चाहते हैं, दूसरे वे जो कुछ होना चाहते हैं। असली नेता को सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होकर, प्रासंगिक और अप्रासंगिक के बीच भेदरेखा बनानी होती है। संयुक्त रूप से कार्य करें तो आज भी वे भारत को विकास की नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने सहचिन्तन को शायद कमजोरी मान रखा है। नेतृत्व के नीचे शून्य तो सदैव खतरनाक होता ही है पर यहां तो ऊपर-नीचे शून्य ही शून्य है। इंडिया गठबंधन की चोटी से लेकर प्रांत स्तर पर, समाज स्तर पर तेजस्वी और खरे नेतृत्व का नितान्त अभाव है। यह सोच का दिवालियापन ही है कि दिखते हुए भ्रष्टाचार के बावजूद उसका विरोध नहीं करके, ऐसे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिये लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन हो रहे हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन वह भी उतना सच है कि इस मामले में कोई भी दल दूध का धुला नहीं है। राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं। विपक्षी दल कुछ भी दावा करें, सच्चाई यह है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान उनके पास भी नहीं है। राजनीति में काले धन का इस्तेमाल होता रहा है और कोई भी यह दावे के साथ कहने की स्थिति में नहीं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। जो विपक्षी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं अथवा उन्हें जेल जाना पड़ा है, उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कहीं कुछ गलत नहीं किया। प्रधानमंत्री ने मेरठ में चुनावी महासंग्राम की शुरुआत करते हुए कहा कि अगर विपक्षी नेता पाक-साफ़ हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें छोड़ क्यों नहीं रहा है? कुछ तो गड़बड़ होगी ही। कुल मिलाकर बयानों का तीखापन यहाँ- वहाँ आने लगा है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में धार आ गई है। यह धार दिन ब दिन और पैनी होती जाएगी।

भारत के केनवास पर शांति, प्रेम, ईमानदारी, विकास और सह-अस्तित्व के रंगों की जरूरत है, पर आज इंडिया गठबंधन इन रंगों को भरने की पात्रता खोकर नायकविहीन है। रंगमंच पर नायक अभिनय करता है, राजनीतिक मंच पर नायक के चरित्र को जीना पड़ता है, कथनी-करनी में समानता, दृढ़ मनोबल, इच्छा शक्ति और संयमशीलता के साथ। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की यह एक बड़ी विडम्बना है कि यहां विपक्षी दलों में नायक कम, खलनायक अधिक है। तभी एक मोदी अठाइस दलों के नेताओं पर भारी पड़ रहा है। देखना यह है कि विपक्षी दलों ने राजनीतिक भ्रष्टाचार का मामला उठाकर मोदी सरकार को घेरने की जो कोशिश की, उससे देश की जनता कितनी प्रभावित होगी और इसकी आवश्यकता महसूस करेगी या नहीं कि इस गठबंधन को सत्ता में लाना आवश्यक है। विपक्षी दलों ने जो मुद्दे उठाये, वे प्रभाव पैदा नहीं कर पाये। चुनावी बांड का ही मुद्दा ले, इसमें संदेह नहीं कि चुनावी बांड से दिए जाने वाले चंदे का जो विवरण सामने आया है, उससे अनेक गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जिन कंपनियों का नाम लेकर यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने उन पर अनुचित दबाव डालकर चंदा हासिल किया, उनमें से अनेक ने विपक्षी दलों को भी अच्छा-खासा चंदा दिया है।

सीएम मोहन यादव ने कहा

इंदौर की गेर को यूनेस्को में शामिल कराने के लिए सरकार भी करेगी प्रयास

इंदौर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी गुरुवार को इंदौरी रंग में नजर आए। वे दो घंटे से ज्यादा समय गेर में शामिल हुए। मालवी पगड़ी पहने रंग-गुलाल में तर मुख्यमंत्री खुद लोगों पर गुलाल बरसा कर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। जगह-जगह लोगों पर उन्होंने गुलाल उड़ाया। अभिवादन भी स्वीकार किया। जब लौटे तो रंग और पानी से तरबतर होकर। दोनों हाथ उठाकर वह इंदौर की गेर से रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि गुजरात का गरबा यूनेस्को में शामिल कुछ समय पहले हुआ है। इंदौर के रंगों की इस गेर को भी यूनेस्को से जोड़ने का काम हो रहा है। इसके लिए सरकार भी प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रंगों का यह त्योहार परस्पर भाईचारा बढ़ाने वाला है। हम सब अपने जीवन की कलुष्ता मिटाकर रंगों के त्योहार में डूब जाते है।प्रेम रंग में डूबकर हम तमाम दुश्मनियां भूल जाते है। यह त्योहार शोक निवारण का भी है।होली से लेकर पंचमी तक मालवा में हर दिन आनंद के साथ गुजरता है। इंदौर में तो इसका अंदाज ही निराला है। यहां मालवा के लोग जुटते है।

मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वजह से अब दुनिया हमारी तरफ देख रही है। हमारे देश की कला, संस्कृति, वैभव में अलग ही आनंद और मस्ती है। उन्होंने कहा कि रंगपंचमी भी एक तरह से नए साल की तरह मनाई जाती है। 75 वर्ष से ज्यादा पुरानी इस परंपरा में शामिल होकर मैं बेहद खुश हूं। वर्षों पुरानी परंपरा मध्य प्रदेश के साथ-साथ मालवा की खास है। गेर तो एक शब्द है, यह तो अपना बनाने वाली टोली है। पहले रंगपंचमी पर अलग-अलग समाजों और मोहल्लों के निशान लेकर निकलने की परंपरा भी रही है। आचार संहिता है। कुछ सीमाएं हैं। इसके बाद भी गौरवशाली परंपरा को याद करने मैं आज यहां आया हूं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गेर में शामिल होने से पहले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उनका रंग-गुलाल लगाकर स्वागत किया। डॉ. यादव ने सभी लोगों को रंगपंचमी की शुभकामनाएं दी। फिर हिंद रक्षक की फाग यात्रा में शामिल हुए।

गिरते गिरते बचे सीएम

मुख्यमंत्री जिस वाहन में सवार थे। उसमें एक लिफ्ट भी लगी थी। राजवाड़ा पर वाहन से उतरने से पहले वे खुली लिफ्ट में चढ़कर लोगों पर गुलाल बरसाते रहे। इस दौरान लिफ्ट झटके से नीचे आई तो सीएम का संतुलन बिगड़ गया। वे गिरते-गिरते बचे। इसके बाद सुरक्षा में जुटे अफसरों ने लिफ्ट नीचे उतरवा दी।

स्काउट गाइड के बच्चों द्वारा देव गुराडिया मेले में चार दिन सेवा कार्य

मेले में बेहोश हुई महिला, भारत स्काउट एवं गाइड की टीम ने की मदद

इंदौर। भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश जिला संघ इंदौर के तत्वाधान में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर गुटकेश्वर महादेव मंदिर, देवगुराडिया पर स्काउट गाइड के बच्चों द्वारा सेवाकार्य किया गया। संयुक्त सचिव श्रीमती वैजयंती गहलोत ने बताया कि मंदिर पर कुल 40 स्काउट गाइड अपने 2 प्रभारियों के साथ सेवाकार्य के रूप में मंदिर में दर्शनार्थियों को कतार बनवाकर दर्शन करवाने में सहयोग किया। चोटिल दर्शनार्थियों हेतु प्राथमिक सहायता केंद्र का संचालन भी किया गया। भरी धूप में व्रत की हुई बहुत सी महिलाओं को चक्कर आने पर उन्हें ग्लूकोज व पानी उपलब्ध करवाया गया। उक्त शिविर में आई. ए. टी. वी. एजुकेशनल एकेडमी, महाराजा तुकोजीराव

होलकर स्काउट एवं गाइड ग्रुप व संत जोसेफ स्कूल नंदानगर के स्काउट गाइड ने प्रभारी श्रीमती वैजयंती गहलोत व योगेश जोशी के मार्गदर्शन में सेवाकार्य किया।

सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करके बनाया जाएगा हाईटेक

60 से अधिक स्कूलों के पुनरुद्धार की योजना तैयार

इंदौर। स्मार्ट सिटी इंदौर के बदले सरकारी स्कूलों की अब जल्द ही तस्वीर बदल सकती है। गर्मियों की छुट्टी के बाद शुरू होने वाले शिक्षा सत्र से 60 से अधिक स्कूलों के कायाकल्प की योजना बना ली गई है। इसके लिए बंद पड़े सरकारी स्कूलों की अनुपयोगी जमीन बिल्डरों को दी जाएगी और उसके बदले स्कूलों को हाईटेक बनाने का कार्य किया जाएगा। दरअसल, महानगर में 236 सरकारी स्कूल हैं। इनमें से अधिकांश स्कूलों के भवनों की हालत खस्ता हैं। इन्हें ठीक कराने के लिए बजट भी नहीं है। इसके चलते अब इनकी दशा सुधार कर निजी स्कूलों को टक्कर देने के वास्ते जिला प्रशासन ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत बंद पड़े स्कूलों की अनुपयोगी जमीन बिल्डर को दी जाएगी और इससे मिलने वाली राशि से वहां अत्याधुनिक भवनों का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही अन्य आवश्यक सुविधाएं जुटाई जाएंगी। पहले चरण में होगा 61 स्कूलों का उद्धार सूत्रों के मुताबिक, इस योजना के तहत प्रस्ताव बनाकर अनुमति के लिए सरकार को भेजा जा रहा है। पुर्नघनत्वीकरण योजना के तहत अनुमति मिलने के बाद इन स्कूलों की अनुपयोगी जमीन बिल्डर को सौंपी जाएगी, इसके एवज में बिल्डर स्कूल के लिए अत्याधुनिक एवं सर्वसुविधायुक्त बिल्डिंग का निर्माण करेगा। इसके बाद बिल्डर को जमीन पर बने अन्य निर्माण को बेचने की अनुमति दी जाएगी। बिल्डर को जमीन बेचने से मिलने वाली राशि में से 70-80 फीसदी राशि नगर निगम लेगा और उसे सरकारी स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने पर खर्च करेगा।

जिला प्रशासन ने भू माफियाओं से 400 करोड़ रुपए मूल्य की शासकीय जमीन कराई अतिक्रमण मुक्त

इंदौर। इंदौर में आज भू माफियाओं से बेशकीमती शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन के अमले द्वारा नगर निगम के सहयोग से बड़ी कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में की गई। इस कार्यवाही में तहसील राऊ के ग्राम तेजपुर गड़बड़ी की अन्नपूर्णा मंदिर के समीप स्थित 4.967 हेक्टेयर शासकीय भूमि भू माफियाओं से अतिक्रमण मुक्त की गई। इस भूमि का बाजार मूल्य 400 से 450 करोड़ रुपये अनुमानित है। अपर कलेक्टर सपना लोवंशी ने

बताया कि तहसील राऊ के ग्राम तेजपुर गड़बड़ी स्थित भूमि सर्वे नंबर 56, 57, 58, 59, 99/1 कुल रकबा 4.967 हेक्टेयर जिसका लैण्डयूज पीएसपी एवं रेसीडेंशियल है। गाईड लाईन वेल्यू 118.21 करोड़ है तथा वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 400 से 450 करोड़ है। भूमाफियाओं द्वारा वर्ष 2000 से शासन द्वारा जारी परिपत्रों का गलत दुरूपयोग करते हुए इंदौर शहर के बीचोबीच स्थित भूमियों पर लगभग 25 खण्डहरनुमा छोटे-छोटे कमरे बना रखे थे जो कि लगभग 100 फीट दूर स्थित थे। उक्त कमरों में बिजली, पानी, सिवरेज लाईन, सड़क आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी। अतिक्रमण कर्ताओं द्वारा अवैध कालोनी दिखाकर व्यवस्थापन का लाभ लेने के उद्देश्य से भूमियों को हड़पने का षड्यंत्र रचा जा रहा था तथा शासन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था।

6 सीट पर 113 प्रत्याशी मैदान में

पांच पर भाजपा-कांग्रेस में सीधी टक्कर, एक पर त्रिकोणीय मुकाबला

***भोपाल।** प्रदेश की छह लोकसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने का काम 27 मार्च को पूरा हो गया। अब 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इन सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन छह सीटों पर कुल 113 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन छह सीटों में से छिंदवाड़ा को छोड़कर पांचों सीटें फिलहाल भाजपा के कब्जे में है। सत्तारूढ़ भाजपा इस बार ये सभी छह सीटें जीतने में जुटी है, हालांकि विधानसभा चुनाव के नतीजों को देख विश्लेषण करें तो तीन सीटों मंडला, छिंदवाड़ा व बालाघाट में कांग्रेस कड़ी टक्कर दे सकती है, जबकि सीधी, शहडोल व जबलपुर में भाजपा मजबूत स्थिति में है। सियासी जानकारों का कहना है कि भाजपा 400 पार के लक्ष्य को लेकर बढ़ रही है और वह एक बार फिर राम और मोदी लहर के दम पर प्रदेश की सभी सीटों पर जीत के प्रति आश्वस्त है।*

सीधी- यहां मुकाबला भाजपा के राजेश मिश्रा और कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल के बीच है। हालांकि, भाजपा के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने बागी होकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (गोंगपा) से नामांकन भरा है। अजय प्रताप सिंह सीधी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन भाजपा ने राजेश मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। यहां पर अजय प्रताप सिंह के नाम

वापस नहीं लेने पर मुकाबला रोचक हो सकता है। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक कमलेश्वर पटेल को टिकट दिया है। सीधी संसदीय क्षेत्र में आठ विधानसभा सीटें हैं। इसमें चुरहट, सीधी, सिंहावल, चितरंगी, सिंगरौली, देवसर, धौहानी, ब्यौहारी शामिल हैं। चुरहट सीट कांग्रेस ने जीती है बाकी सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा है।

जबलपुर- इस सीट पर कांग्रेस के दिनेश यादव और भाजपा के आशीष दुबे के बीच टक्कर है। कांग्रेस ने 10 साल से जबलपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष को प्रत्याशी बनाया है। यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। जबलपुर में कांग्रेस का बड़ा चेहरा हैं। पार्षद रह चुके हैं। पीसीसी के महामंत्री भी रहे हैं। वहीं, यहां से भाजपा ने आशीष दुबे को प्रत्याशी बनाया है। वे केंद्रीय नेतृत्व के करीबी हैं। इस सीट से राकेश सिंह को विधानसभा का चुनाव लड़ाया था। चुनाव जीतने के बाद राकेश सिंह ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वे प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। जबलपुर में आठ विधानसभा सीटें हैं। इसमें पाटन, बरगी, जबलपुर पूर्व, जबलपुर उत्तर, जबलपुर कैंट, जबलपुर पश्चिम, पनागर और सिहोरा सीट शामिल हैं। इनमें से सिर्फ एक सीट जबलपुर पूर्व कांग्रेस के कब्जे में है।

मंडला (एसटी)- यहां पर मुकाबला केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस के विधायक ओमकार सिंह मरकाम के बीच है। कुलस्ते को भाजपा ने निवास सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ाया था, लेकिन वे चुनाव हार गए। ओंकार सिंह मरकाम डिंडौरी से विधायक हैं। मरकाम वर्तमान में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं। इस संसदीय क्षेत्र में आठ विधानसभा सीटें हैं। इसमें डिंडौरी, बिछिया, निवास, केवलारी, लखनादौन, शहपुरा, मंडला और गोटेगांव शामिल हैं। इसमें से पांच सीटें कांग्रेस और तीन पर भाजपा का कब्जा है। इसमें छह सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। जिसमें चार कांग्रेस ने जीतीं।

छिंदवाड़ा- इस सीट पर कांग्रेस के सांसद नकुलनाथ और भाजपा के युवा नेता विवेक बंटी साहू के बीच मुकाबला है। छिंदवाड़ा सीट जीतने के लिए भाजपा पूरा जोर लगा रही है। कमलनाथ और नकुलनाथ के भाजपा में शामिल नहीं होने के बाद अब भाजपा ने उनके करीबियों को भाजपा में शामिल करने की रणनीति अपनाई है। पिछली बार कांग्रेस ने जीती इस एकमात्र सीट पर नकुलनाथ करीब 37 हजार वोटों से जीते थे। ऐसे कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस के लिए छिंदवाड़ा सीट बचाना चुनौती पूर्ण हो सकता है। वहीं, बंटी साहू छिंदवाड़ा में भाजपा के बड़े नता है और युवाओं में उनकी अच्छी पकड़ है। इस संसदीय क्षेत्र में सात विधानसभा सीटें आती हैं, जिन पर कांग्रेस का कब्जा है। इसमें जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, चौरई, सौसर, छिंदवाड़ा, परासिया और पांडुर्णा शामिल है।

शहडोल (एसटी)- इस सीट पर कांग्रेस के फुंदेलाल मार्को और भाजपा की हिमाद्री सिंह के बीच मुकाबला है। हिमाद्री सिंह शहडोल से सांसद हैं। वहीं, मार्को पुष्पराजगढ़ आरक्षित सीट से विधायक हैं। वे तीन बार के विधायक और आदिवासियों के बड़े नेता हैं। उनकी ताकत जमीनी और जनता से जुड़ा होना है। वे अधिकतर अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित शहडोल संसदीय क्षेत्र में आठ विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें जयसिंहनगर, जैतपुर, कोतमा, अनुपपुर, पुष्पराजगढ़, बांधवगढ़, मानपुर और बड़वारा सीट है। इनमें से सात सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। एक सीट पर कांग्रेस का कब्जा है।

बालाघाट- यहां पर कांग्रेस के युवा नेता सम्राट सारस्वत और भाजपा की भारती पारधी के बीच मुकाबला है। भाजपा ने सांसद ढाल सिंह बिसेन का टिकट काटकर पार्षद भारती पारधी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं, कांग्रेस ने जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट पर भरोसा जताया है। वह पूर्व विधायक अशोक सारस्वत के बेटे हैं और राजपूत समाज से आते हैं। इस संसदीय क्षेत्र में आठ विधानसभा सीटें बैहर, लांजी, परसवाड़ा, बालाघाटा, वारासिवनी, कटंगी, बरघाट और सिवनी आती हैं। यहां चार-चार सीटें भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जीती हैं। वहीं, दो आरक्षित सीट में से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बैहर सीट पर कांग्रेस और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित बरघाट सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की है।

मप्र में भाजपा के खिलाफ एक मुद्दा खड़ा नहीं कर पाई कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को मनाने में ही जुटे

भोपाल। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 20 दिन बाद 19 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन मप्र में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस अभी तक भाजपा सरकार के खिलाफ एक मुद्दा खड़ा नहीं कर पाई है। चुनाव के मुद्दों को लेकर कांग्रेस के नेता एकजुट भी नहीं दिख रहे है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सिर्फ किसानों को भाजपा की चुनावी घोषणा अनुसार फसल की कीमत देने की मांग कर तो रहे हैं, लेकिन इसे मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। यूं तो देश में हर चुनाव मुद्दों के आधार पर ही लड़ा जाता है, लेकिन इस बार अभी तक मप्र में विपक्ष के हाथ कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। उल्टा भ्रष्टाचार, गुटबाजी एवं अन्य पुराने मामलों को लेकर भाजपा ही कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दे रही है।

सडक़ से लेकर सदन तक मुद्दा विहीन कांग्रेस-ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव के दौरान ही मुद्दों को नहीं उठा पा रही है। बल्कि विधानसभा सत्र के दौरान भी कांग्रेस जनता की समस्याओं को उतनी पुरजोर तरीके से उठाने में नाकाम रही है। जितनी दमदारी से भाजपा विपक्ष

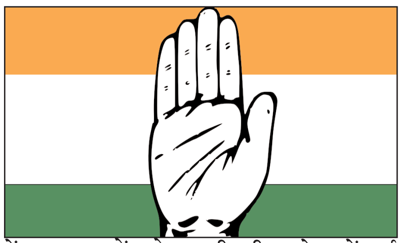

में रहकर मुद्दों को उठाती थी। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद विधानसभा के दो सत्र बीत चुके हैं। जिनमें पहला सत्र सदस्यों के शपथ समारोह के लिए था। दूसरा सत्र फरवरी में आयोजित हुआ। जिसमें अनुपूरक बजट समेत अन्य विधेयक पास किए गए। पूरे सत्र के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस ने एक भी मुद्दा ऐसा नहीं उठाया, जिसने सरकार को परेशानी में डाला हो। इसके बाद सदन के बाद सडक़ पर भी कांग्रेस कोई मुद्दा नहीं उठा पाई है। कांग्रेस ने अभी तक एक भी ऐसा कोई आंदोलन या प्रदर्शन नहीं किया, जिसमें लोगों की भागीदारी रही हो। कुछ मामलों में कांग्रेस के नेता प्रदर्शन की सिर्फ खानापूर्ति करते रहे हैं।

रोज कमजोर हो रही कांग्रेस-मप्र में कांग्रेस रोजाना कमजोर हो रही है। क्योंकि प्रदेश के किसी न किसी हिस्से से कांग्रेस के पूर्व विधायक, सांसद, मंत्री या अन्य कोई पदाधिकारी पार्टी छोड़ रहे हैं। चुनाव के दौरान नेता और कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने से जनता के बीच विपरीत संदेश जाता है। जिससे चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। पार्टी में जारी भगदड़ की वजह से नेता सरकार के खिलाफ कोई चुनावी मुद्दा खड़ा नहीं कर पाए हैं।

प्रदेश प्रभारी ने मप्र से बनाई दूरी

कांग्रेस नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को मप्र की जिम्मेदारी से हटा दिया था। इसके बाद जितेन्द्र सिंह को मप्र का प्रभार सौंपा गया। शुरूआत में जितेन्द्र सिंह ने मप्र में सक्रियता दिखाई थी। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उन्होंने मप्र से लगभग दूरी बना ली है। वे मप्र में उतने सक्रिय नहीं दिख रहे, जितने शुरू में थे। पिछले एक पखवाड़े से ज्यादा समय से जितेन्द्र मप्र दौरे पर ही नहीं आए। हालांकि वे दिल्ली में ज्यादा समय पार्टी को दे रहे हैं। मप्र के नेताओं से भी वहीं मुलाकात कर रहे हैं।

उपाय एप के जरिए होगा विद्युत शिकायत का समाधान

भोपाल। विद्युत संबंधी शिकायत के निराकरण के लिये उपाय एप के माध्यम से आसानी से समाधान किया जा रहा है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में उपाय एप डाउनलोड करना होगा। आंधी, तूफान एवं अन्य कारणों से होने वाले विद्युत व्यवधान के निराकरण के लिए भी उपभोक्ता मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपाय एप को डाउनलोड कर अपनी शिकायत का त्वरित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी ने बताया है कि बिजली उपभोक्ता गूगल प्ले स्टोर से इस एप को नि:शुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। उपभोक्ता मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपाय एप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करने के साथ ही शिकायत की स्थिति भी जान सकते हैं। साथ ही बिजली बिल भी आसानी से घर बैठे ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए उपाय एप के अनेक फायदे हैं। उपाय एप के रजिस्टर कम्पलेंट ऑप्शन्स की सहायता से विद्युत व्यवधान या बिल संबंधी शिकायत दर्ज कर शिकायत क्रमांक प्राप्त कर सकते हैं।

शिकायत के निराकरण की स्थिति भी उपाय एप के माध्यम से जान सकते हैं। अपने वर्तमान बिल को डाउनलोड करने के साथ ही बिल भुगतान भी किया जा सकता है। उपाय एप से बिल का भुगतान करने पर उपभोक्ता को बिल डेस्क, एचडीएफसी बैंक पे-यू, गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग इत्यादि ऑप्शन्स प्राप्त होते हैं। उपभोक्ता इनमें से किसी भी एक माध्यम का चयन कर अपने बकाया विद्युत बिल का भुगतान कर तुरंत पावती प्राप्त कर सकते हैं।

डैमेज कंट्रोल, चुनाव का टिकट कटा तो मायूस दिग्गजों को बनाया 'स्टार प्रचारक'

पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और कांग्रेस ने पूर्व विधायक हिना कावरे को अपने-अपने दल का स्टार प्रचारक नियुक्त किया

***भोपाल।** कहते हैं, राजनीति में तस्वीर बदलते देर नहीं लगती। जिले की राजनीति में भी यही हालात हैं। लोकसभा चुनाव में सांसद बनने का सपना बुनने वाले दिग्गज नेता इन दिनों मायूसी की चादर ओढ़े गम मना रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी आलाकमान उनके दुख को कम करने में जुटी है ताकि दिग्गजों की नाराजगी कहीं पार्टी के नुकसान का कारण न बन जाए।*

भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी-अपनी पार्टी में 'डैमेज कंट्रोल' किया है। सांसद का टिकट न मिलने से मायूस इन नेताओं को पार्टी ने अपना 'स्टार प्रचारक' बनाया है। हालांकि, स्टार प्रचारक बनाने से नेताओं की टिकट न मिलने की टीस भले ही कम न हो, लेकिन उनके जख्मों पर पार्टी ने जरूर मलहम लगाने का काम किया है। भाजपा ने पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और कांग्रेस ने पूर्व विधायक हिना कावरे को अपने-अपने दल का स्टार प्रचारक नियुक्त किया है। अब दोनों नेता अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने में जुट गए हैं। हालांकि, स्टार प्रचारकों के मन में दबा पड़ा दुख, कहीं न कहीं प्रचार-प्रसार में जोश की कमी को उजागर कर रहा है।

'भाऊ' और बेटी की मुराद रह गई अधूरी

गौरीशंकर बिसेन यानी 'भाऊ' इस बार भी टिकट की आस लगाए बैठे थे। खुद के लिए ही न सही, कम से कम बेटी मौसम हरिनखेड़े को टिकट दिलाने भाऊ ने भरसक प्रयास किए। टिकट वितरण से पहले ये खबर भी चर्चा में रही कि भाऊ दिल्ली और भोपाल के दौरे कर रहे हैं, लेकिन हुआ वही, जो पार्टी ने तय कर रखा था। वार्ड-22 की पार्षद भारती पारधी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस घोषणा के साथ ही 'बिसेन' परिवार का टिकट को लेकर संजोया गया सपना चकनाचूर हो गया। बिसेन परिवार को टिकट न मिलने के पीछे कई वजहें गिनाई जा रही हैं। बिसेन को टिकट न मिलने के पीछे बड़ा कारण उनकी उम्र है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में मौसम को टिकट दिलाने के लिए बने उठा-पटक के हालात ने पार्टी में भाऊ के प्रति नकारात्मक छवि पैदा की थी। पहले भाऊ ने मौसम को टिकट दिलाने ऐड़ी-चोटी का जोर लगाया। न चाहकर भी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन आखिरी समय में भाऊ खुद मैदान में उतर आए और 29 हजार से अधिक वोटों से हार गए। विधानसभा चुनाव में इस किरकिरी ने पार्टी को लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर फैसला बदलने पर विवश कर दिया और भाऊ और बेटी की टिकट की मुराद अधूरी रह गई। अब पार्टी ने भाऊ को स्टार प्रचारक बनाकर उनके सम्मान को बनाए रखा है।

टिकट कटते ही उड़ी हिना की रंगत

बात करें कांग्रेस की तो यहां से पूर्व विधायक हिना कावरे इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रबल दावेदारी मानी जा रही थीं। स्वयं हिना भी टिकट को लेकर आश्वस्त थीं, लेकिन पार्टी ने नामांकन के आखिर दिनों तक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की, तब लोगों को 'दाल में कुछ काला' नजर आया और जो सोचा, वही हुआ। पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार को उम्मीदवार बना दिया। इस फैसले ने हिना की रंगत ही उड़ा दी। आनन-फानन में हिना कावरे और उनके समर्थक विधायक दिल्ली पहुंच गए और फैसला बदलने की बात रख दी। हिना की नाराजगी का सबूत बुधवार को नामांकन रैली के दौरान तब दिखा, जब प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंच से पार्टी में 'डैमेज कंट्रोल' करने का प्रयास किया। उन्होंने हिना को आश्वस्त किया कि उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा पद मिलेगा। यानी कांग्रेस ने भी हिना कावरे की नाराजगी को दूर करने बड़े पद के आश्वासन के साथ स्टार प्रचारक बनाकर इस नाराजगी को कम करने का प्रयास किया है।

आमचुनाव के दौरान पार्टी प्रवक्ताओं को हटाया, भुगतना पड़ सकता है नुकसान

भोपाल। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल होने का जो दौर शुरु हुआ है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस से मीडिया प्रवक्ताओं को हटाकर नए चेहरों की भर्ती की गई है, जिससे चुनाव में पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस द्वारा जारी की गई नई सूची में पहले से कार्य कर रहे प्रवक्ताओं को शामिल नहीं किया गया है, जिससे उनमें नाराजगी देखी जा रही है, वहीं एक बुजुर्ग को मीडिया सलाहकार बनाए जाने को लेकर भी विरोधी स्वर फूटने लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदलने और जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही कयास लगाए जा रहे थे कि पहले से जमें पदाधिकारियों को हटाया जाएगा और नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। अब जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने अपनी टीम घोषित करते हुए जो सूची जारी की है, उसमें पुराने मीडिया प्रवक्ताओं के नाम सिरे से गायब कर दिए गए हैं। इससे पूर्व मीडिया प्रवक्ताओं में खासा रोष व्याप्त है। हटाए गए पदाधिकारियों का कहना है कि इस चुनावी माहौल में यूं पदाधिकारियों का बदला जाना कहीं से भी पार्टी के फेवर में नहीं है। चुनाव में बेहतर रिजल्ट के लिए कार्य करने की बजाय पार्टी नेतृत्व पदाधिकारियों को बदलने में व्यस्त है। ऐसे में अनुभवी लोगों को पद से हटाकर नए लोगों की भर्ती करना कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

स्वयं मतदान करें, परिवार, पास-पड़ोस के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें

भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने रविवार को मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने आगामी 7 मई को भोपाल लोकसभा सीट के लिए होने वाले मतदान में सभी नागरिकों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। उन्होंने प्रदेश के सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि खुद मतदान करें और परिवार, पास पड़ोस के नागरिकों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर भोपाल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह, सीईओ जिला पंचायत एवं नोडल स्वीप ऋतुराज, आयुक्त नगर निगम हरेंद्र नारायण सहित रैली में अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

लालघाटी चौराहे से हुआ रैली का शुभारंभ-भोपाल का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित मतदाता जागरूकता वाहन रैली का सुबह 7:30 बजे लालघाटी चौराहे से शुभारंभ हुआ। यह रैली वीआईपी रोड, गौहर महल, जहांगीराबाद होते हुए शौर्य स्मारक, अरेरा हिल्स पहुंची। शौर्य स्मारक पर रैली का समापन हुआ। रैली में शामिल विभिन्न बाइकर्स ग्रुप, क्लब के सदस्यों सहित 2500 से अधिक नागरिकों ने रैली में मतदाता जागरूकता का संदेश दिया।

मप्र सरकार के पास जल्द होगा खुद का विमान

भोपाल । मप्र सरकार के पास अभी खुद का विमान नहीं है। कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने विमान खरीदा था पर वह दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद खराब पड़ा है। शिवराज सरकार ने नया विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरु की लेकिन इसमें अड़ंगे आते रहे। ऐसे में जरूरत के समय निजी विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन जल्द ही यह दिक्कत दूर होनेवाली है। भाजपा की मोहन यादव सरकार नया जेट विमान खरीद रही है। बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश सरकार एक हाईक्लास विमान खरीद रही है। इसके लिए कई कंपनियों ने रुचि दिखाई है। राज्य सरकार करीब 200 करोड़ रुपये का जेट विमान लेगी। विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। जेट प्लेन खरीदने की राज्य सरकार की बहुत इच्छा है। दरअसल इसके लिए 2 साल से कोशिश की जा रही है लेकिन कोई न कोई अड़ंगा लगता रहा है। विमानन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शिवराज सरकार ने तो जेट प्लेन के लिए एक अमेरिकन कंपनी से बात भी कर ली थी। 150 करोड़ का बजट प्रावधान भी कर लिया था। विमान नहीं होने से राज्य सरकार को खासी दिक्कत आ रही है। यही कारण है कि मोहन यादव के सीएम बनने के बाद जेट प्लेन के लिए पूर्व निविदा जारी की गई। मप्र सरकार नया जेट प्लेन खरीदने की तैयारी कर रही है। लगभग 200 करोड़ रुपए की कीमत में खरीदे जाने वाले सात सीटर मिड साइज जेट विमान में कई अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। इसमें दो पायलट रहेंगे और उनके अलावा विमान में दस लोग बैठ सकेंगे। 5 हजार फीट की हवाई पट्टी पर भी यह जेट विमान उतर सकेगा। जेट विमान करीब 500 समुद्री मील की गति से उड़ता है।

होली के बाद परदे पर धमाल मचाएंगी ये जोड़ियां

सिध्दार्थ मल्होत्रा की फिल्म अयोध्या होली से पहले बड़े परदे पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फिल्म में सिध्दार्थ पहली बार दिशा पाटनी के साथ नजर आ रहे हैं। बी टाउन की यह नई जोड़ी ऑडियन्स को कितना इम्प्रेस कर पाएंगी, यह सवाल इस वक्त सभी के दिलों में है।

बता दें कि इस साल होली के बाद बड़े परदे पर कई नई जोड़ियां नजर आने वाले हैं। चलिए नजर डालते हैं इस साल फिल्मी परदे पर पहली बार धमाल मचाने के लिए तैयार जोड़ियों पर।

कार्तिक आर्यन-तृप्ति डिमरी फिल्म एनिमल से नेशनल क्रश बन चुकी तृप्ति डिमरी इस साल बड़े परदे पर कार्तिक आर्यन के साथ नजर आने वाली हैं। फिल्म भूल भुलैया 3 में इनकी जोड़ी बनने जा रही है। भूल भुलैया 3 में विद्या बालन की भी वापिसी हो रही है। भूल भुलैया 2 में कार्तिक और कियारा की जोड़ी फैंस को काफी पसंद आई थी। ऐसे में कार्तिक और तृप्ति को साथ देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं।

दीपिका पादुकोण- प्रभास

साउथ के सुपरस्टार प्रभास की बी टाउन की मस्तानी दीपिका पादुकोण की पेयरिंग भी इस साल स्क्रीन पर नजर आएगी। ये दोनों पहली बार साथ काम करने जा रहे हैं। फिल्म कल्कि 2898 एडी में दोनों साथ नजर आएंगे। फैंस को इनकी जोड़ी से काफी उम्मीदें हैं।

कियारा आडवाणी- रणवीर सिंह

इस साल यह नई जोड़ी भी फिल्मी परदे पर धमाल मचान के लिए तैयार है। ये दोनों डॉन 3 में नजर आने वाले हैं। डॉन फ्रेंचाइज से शाहरुख खान के जाने और रणवीर की एंट्री से फैंस खासा खुश नहीं थे। ऐसे में अब देखना होगा कि यह नई जोड़ी ऑडियन्स को कितना इम्प्रेस कर पाती है।

रश्मिका मंदाना- विक्की कौशल

फिल्म एनिमल में रश्मिका और रणबीर कपूर की जोड़ी नजर आई थी। हालांकि, फिल्म की कहानी की वजह से इन दोनों की केमिस्ट्री को लेकर कुछ खास चर्चा नहीं हुई थी। अब रश्मिका फिल्म छांवा में विक्की कौशल के साथ नजर आएंगी। देखना होगा कि इस फिल्म में इनकी जोड़ी को ऑडियन्स का प्यार मिलता है या नहीं।

अपने दूसरे बच्चे को लेकर रानी मुखर्जी का झलका दर्द

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी और निर्देशक आदित्य चोपड़ा इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा कपल में से एक माने जाते हैं। दोनों की शादी को काफी समय हो चुका है। दोनों की एक बेटी अदिरा है। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपने हालिया इंटरव्यू में उनकी साल 2023 में आई फिल्म मिसेज चटर्जी VS नॉर्वे के लिए साइन करने से ठीक पहले महामारी के दौरान हुए अपने दर्दनाक गर्भपात के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत दुखद है, क्योंकि वे आदिरा को एक भाई या बहन नहीं दे सकती। हाल ही में एक मीडिया बात करते हुए रानी मुखर्जी ने बताया, मैंने सात साल तक अपने दूसरे बच्चे के लिए ट्राई किया। मेरी बेटी अब 8 साल की है। उसके तुरंत बाद, मैंने अपने दूसरे बच्चे के लिए कोशिश की। इसके बाद भी मैं कोशिश करती रही। आखिरकार मैं प्रेग्नेंट हो गई और फिर मैंने बच्चे को खो दिया। जाहिर है ये मेरे लिए परीक्षा की घड़ी थी। रानी ने बात करते हुए आगे बताया, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे पास जो कुछ है उसके लिए मुझे आभारी होना चाहिए, ये एक कहावत है, लेकिन असल में इस पर काम करने और ये विश्वास करने के लिए कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको आभारी होना चाहिए, इसके लिए बहुत साहस की जरूरत होती है, जो आपके पास है बस उसी में संतुष्ट रहना। इसलिए मैं इस पर काम कर रही हूं।

प्रर्वतन निदेशालय में नौकरी

जानें ईडी ऑफिसर के लिए

योग्यता और चयन प्रक्रिया

शराब घोटाले के आरोप में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बीते दिनों गिरफ्तार कर लिया। ईडी यानी की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसे प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं। किसी भी घोटाले आदि में छापेमारी और गिरफ्तारी करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय का ही नाम आता है। आइए जानते हैं कि ईडी में नौकरी कैसे मिलती है, योग्यता क्या होनी चाहिए और चयनित कैंडिडेट को कितने रुपए सैलरी हर माह मिलती हैं।

ED या प्रवर्तन निदेशालय

प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेन्सी है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ईडी के प्रमुख कार्यों में फेमा, 1999 के उल्लंघन से संबंधित मामले, हवाला लेन देन और फॉरेन एक्सचेंज रैकेटियरिंग आदि के मामले की जांच करना शामिल है।

ED के कार्य –

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) : यह एक आपराधिक कानून है जिसे धन शोधन को रोकने के लिए और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने और उससे जुड़े मामलों के लिए बनाया गया है। प्रवर्तन-निदेशालय को अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति की जांच करने, संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न करने, अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और विशेष अदालत द्वारा संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करवाते हुए पीएमएलए प्रावधानों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी दी गई है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) – यह एक नागरिक कानून है जो विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय को विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के उल्लंघनों की जांच करने, कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देने और उन पर जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी दी गई है।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफ.ई.ओ.ए): यह कानून आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर भागकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधी, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए देश से भाग गए हैं, उनकी संपत्तियों को कुर्क करने और केंद्र सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी देता है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (फेरा) के अंतर्गत एफइआरए के तहत मुख्य कार्य और इस अधिनियम के कथित उल्लंघनों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है, जिसके आधार पर संबंधित अदालतों में जुर्माना लगाया जा सकता है और एफइआरए के तहत शुरू किए गए मुकदमों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

ऐसे मिलती है ED में नौकरी

ED में ग्रुप ए, बी और सी के विभिन्न पदों पर भर्तियां की जाती है जिनमें से कुछ पदों पर डेप्यूटेशन के आधार पर जबकि कुछ पदों पर प्रोन्नति और भर्ती प्रक्रिया के आधार पर भर्ती की जाती है। ग्रुप ए के पदों पर डेप्यूटेशन बेसिस पर भर्तियां की जाती हैं इसके अंतर्गत स्पेशल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, आदि पद आते हैं जबकि ग्रुप बी के कुछ पदों पर प्रमोशन से और अन्य पर सीधी भर्ती की जाती है। ग्रुप बी के असिस्टेंट एन्फोर्समेंट ऑफिसर पद के लिए स्स्ट द्वारा एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती होती है और ग्रुप सी के पदों के लिए ED द्वारा समय-समय पर भर्ती प्रक्रिया के आधार पर भर्ती की जाती है।

ED AEO पदों के लिए योग्यता–

ED में सहायक प्रवर्तन अधिकारी बनने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को SSC CGL की परीक्षा पास करनी होती है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए और अभ्यर्थियों की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, कुछ विशेष पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष भी होती है। अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट दी जाती है।

एविएशन फील्ड में बना सकते हैं बेहतरीन करियर

अगर आप 12वीं पास करने के बाद कुछ बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज है कि किस फील्ड में जाना चाहिए तो आपके लिए ये आर्टिकल बेहद काम का हो सकता है। आप पायलट बनकर आसमान में ऊंची उड़ान भर सकते हैं। इस क्षेत्र में करियर बनाने के बारे में कम ही लोग सोचते हैं, क्योंकि जानकारी का अभाव रहता था। हालांकि, आजकल करियर के लिहाज से युवाओं के पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं। पायलट बनने के बाद आप लाखों रुपये तक कमा सकते हैं। अगर आप समय रहते इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के बारे में सोचते हैं तो आप जल्दी ही करियर में ग्रोथ भी पा सकते हैं. इस फील्ड में सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में अवसरों की भरमार है।

क्वालिफिकेशन

इस फील्ड में करियर बनाने के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट्स के साथ कम से कम 50 प्रतिशत अंकों से पास

होना जरूरी है। इसके बाद किसी एविशन संस्थान में एडमिशन के लिए एंट्रेस एग्जाम, मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करना होगा। इन सभी राउंड को क्लियर करने के बाद आपको इंस्टिट्यूट में दाखिला मिल जाता है। यहां पर आपको प्लेन से जुड़ी बारीकियां सिखाने के साथ ही उसे उड़ाने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है।

एयरफोर्स जॉइन करने का मौका

इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपको 12वीं के बाद यूपीएससी एनडीए एग्जाम, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम एग्जाम पास करना होगा, जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों को इंडियन एयरफोर्स द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं, बतौर पायलट इंडियन एयरफोर्स में नौकरी पाने के लिए कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम भी दे सकते हैं।

कमर्शियल पायलट

12वीं के बाद एविएशन संस्थान से ट्रेनिंग लेकर कॉमर्शियल पायलट भी बन सकते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए फिटनेस टेस्ट और रिटेन एग्जाम देना पड़ता है। इसके बाद सफल कैंडिडेट्स कमर्शियल पायलट के तौर पर अपना करियर शुरू कर सकते हैं।

GENERAL KNOWLEDGE

– **दुनिया** के किस देश में सबसे ज्यादा मीट खाया जाता है?

उत्तर– अमरीका और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा मांस खाया जाता है।

– भगवान श्रीराम को सुग्रीव के बारे में किसने बताया था?

उत्तर– भगवान श्रीराम को सुग्रीव के बारे में शबरी ने बताया था।

–आखिर लक्ष्मण जी किस शक्ति बाण से मूर्छित हो गए थे?

उत्तर– लक्ष्मण जी वीरघातिनी शक्ति बाण से मूर्छित हो गए थे।

– क्या आप बता सकते हैं कि आखिर अंगद और सुग्रीव के बीच क्या रिश्ता था?

उत्तर– अंगद और सुग्रीव के बीच चाचा और भतीजे का रिश्ता था।

– बताएं आखिर हनुमान जी के पुत्र का नाम क्या है?

उत्तर– हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज था।

–पीले रंग की नदी किस देश में बहती है?

उत्तर– चीन में बहने वाली हुआंग ही नदी पीले रंग की नदी है।

–कौन का विटामिन सर्दी–जुकाम से शरीर की रक्षा करता है?

उत्तर– विटामिन– और विटिमिन – हमारी इम्यूनिटी को मजबूत रखते हैं।

– क्या आप बता सकते हैं कि आखिर वो कौन सा जीव है, जो कभी नहीं मरता, वह हमेशा जिंदा रहता है?

उत्तर– जेलिफिश ही वो जीव है, जो कभी नहीं मरती, वह हमेशा जिंदा रहती है।

–राष्ट्रीय हथियार दिवस कब मनाया जाता है?

उत्तर– राष्ट्रीय हथियार दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है।

–वह कौन सा देश है जहां इंसानों से ज्यादा कंगारू पाए जाते हैं?

उत्तर– ऑस्ट्रेलिया वो देश है, जहां इंसानों से ज्यादा कंगारू पाए जाते हैं।

–दुनिया में सबसे ज्यादा त्यौहार किस देश में मनाए जाते हैं?

उत्तर– दुनिया में सबसे ज्यादा त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं।

– पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है?

उत्तर– पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है।

– वह कौन सा पेड़ है जिसके नीचे खड़े हुए तो जल जाएंगे?

उत्तर – इस पेड़ का नाम मैंशीनील है। वहीं इसका फल खाने से इंसान की मौत भी हो सकती है।

पूरी दुनिया में पहचानी गई इंदौर की गेर

इंदौर। रंगों का उत्सव रंगपंचमी इंदौर में बेहद खास तरीके से मनाया जाता है। एक ही जगह पर इकठ्ठा लाखों लोग एक रंग, एक आवाज और एक राष्ट्र बनकर भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। इंदौर में निकलने वाली गेर न सिर्फ उत्साह, उत्सव की पहचान है बल्कि इंदौरियत का सही अर्थ समझाती है। इस साल की गेर इसलिए भी बेहद खास रही क्योंकि दुनियाभर के देशों के 80 से अधिक एनआरआई गेर को देखने के लिए इंदौर आए। पूरी दुनिया में इस बार गेर की चर्चा रही। प्रशासन ने पूरा प्रयास किया कि इस बार गेर को सभी मानकों पर पूरा करके यूनेस्को की विरासतों में सूचीबद्ध करवाया जा सके। मुख्यमंत्री मोहन यादव के गेर में आने से इस बार यह आयोजन राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना।

प्रचार का असर दिखा दुनियाभर से आए लोग

प्रशासन ने इस साल गेर का दुनियाभर में प्रचार किया। इसका असर भी दिखा और कई देशों से एनआरआई गेर को देखने के लिए इंदौर आए। देश के विभिन्न शहरों से भी लोग इंदौर पहुंचे। प्रतिनिधि से बातचीत में सारंगपुर से आई रचना शर्मा ने बताया कि वे पहली बार गेर देखने के लिए परिवार के साथ इंदौर आई हैं। उन्होंने कहा कि यहां का दृश्य अद्भुत है। हमने कभी नहीं सोचा था कि लाखों लोग इस तरह से रंगों के त्योहार को एक साथ मनाते होंगे। यहां पर हमें बहुत आनंद आया।

यूनेस्को की सूची में शामिल करने पर फोकस

कलेक्टर आशीष सिंह ने अखबार से बातचीत में कहा कि गेर में पहली बार बुकिंग सिस्टम लांच किया गया। लोगों को गेर देखने के लिए छत पर बैठने की जगह दी गई। विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि गेर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया जा सके।

लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार का माध्यम बनी गेर

इस साल गेर में नेताओं ने बहुत अधिक समय दिया। लोकसभा चुनाव से पहले आई गेर में भाजपा के लगभग सभी नेता पूरी तरह से सक्रिय दिखे। मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत सभी भाजपा विधायकों ने गेर में तीन से पांच घंटे का समय दिया। मुख्यमंत्री ने खुद गेर में तीन घंटे से अधिक का समय बिताया। गेर के रास्ते में भी हर जगह भाजपा विधायकों के होर्डिंग दिखाई दिए।

कई दृश्यों ने इंदौरियत को शर्मसार भी किया

प्रशासन की पूरी व्यवस्था के बावजूद कई लोगों ने गेर में शर्मसार करने वाली हरकतें भी की। चोरी की कई घटनाएं सामने आईं। कई लोगों की जेब से पर्स और गले से चेन गायब हुई। इसके साथ महिलाओं और युवतियों को छेड़ने के मामले भी सामने आए। कई जगह जूते-चप्पल फेंककर मारने से लोगों को चोटें लगी। हुड़दंगियों ने रस्ते चलते लोगों की आंखों में गुलाल के गोले बनाकर मारे जिससे कई लोग घायल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव के राजबाड़ा पर आते ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस बीच कई महिलाएं सड़क पर गिर गईं। पुलिसकर्मियों ने उन्हें उठाकर खाली जगह पर बैठाया।

चप्पे-चप्पे पर पुलिस ने रखी नजर

पुलिस ने गेर के हर चप्पे-चप्पे पर नजर रखी। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की बदौलत ही गेर में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। हर पांच से दस फीट की दूरी पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी थी। पूरे राजबाड़ा क्षेत्र में ड्रोन तैनात किए गए जो सुबह से दोपहर तक हर दृश्य की तस्वीर लेते रहे। पुलिस ने कई हुड़दंगियों को मौके पर सबक भी सिखाया।

इंदौर में भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवार तय, लेकिन नजर नहीं आ रहा चुनावी माहौल

इंदौर। इंदौर में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। भाजपा ने दोबारा सांसद शंकर लालवानी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने नये चेहरे के रूप में अक्षय बम को उम्मीदवार बनाया है। जिले के 28 लाख मतदाता वोटिंग के जरिए उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे, लेकिन उम्मीदवारों ने अभी चुनावी जनसंपर्क शुरू नहीं किया है। वे सिर्फ आयोजनों में जाकर वोटरों की नब्ज टटोल रहे हैं। शहर में भी चुनावी माहौल नजर नहीं आ रहा है। दोनों दलों के कार्यकर्ता भी अभी चुनावी मोड में नहीं आए हैं। इंदौर में 13 मई को मतदान होना है। इंदौर लोकसभा में जिले की नौ विधानसभा सीटें आती हैं। उनके वोटरों से मिलने के लिए उम्मीदवारों के पास सवा महीने

का समय है, लेकिन अभी जनसंपर्क अभियान तय नहीं हुआ है। संगठन स्तर पर भाजपा ने चार बैठकें की हैं, लेकिन उम्मीदवार तय होने के बाद कांग्रेस की एक भी बैठक नहीं हो पाई है।

लालवानी आयोजनों में हो रहे शामिल

भाजपा उम्मीदवार शंकर लालवानी ने अभी गली मोहल्लों में जाकर वोटरों से मिलने के बजाए आयोजनों में शामिल होकर उनसे मिलने की रणनीति बनाई है। वे शनिवार को रंगपंचमी की गेर में भी शामिल हुए। इसके अलावा शोक बैठक, फाग यात्रा व अन्य आयोजनों में भी वे शामिल हो रहे हैं।

कार्यकर्तागणों से मिल रहे है बम

कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम वोटरों के बीच में नया चेहरा हैं। अभी वे कार्यकर्ताओं से मिलने पर फोकस कर रहे हैं। हाल ही में वे दो नंबर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। वे अस्पताल में भर्ती महाकाल मंदिर के पुजारियों से भी मिलने गए थे। इसके अलावा होली मिलन समारोहों और फाग महोत्सवों में भी शामिल हो रहे हैं।

रंग पंचमी की गेर के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर

कलेक्टर आशीष सिंह ने शहर वासियों के प्रति किया आभार व्यक्त

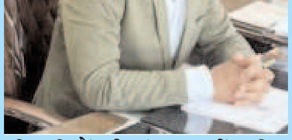

इंदौर। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने इंदौर के परंपरागत पर्व रंग पंचमी पर निकलने वाली गेर के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए शहर वासियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने पूरी टीम इंदौर को गेर के निर्विघ्न समापन की बधाई दी है। इस बार प्रतिभागियों की संख्या कहीं अधिक थी और वीआईपी विजिट भी थी। इसके बाद भी सभी व्यवस्थाएँ उत्कृष्टतम रहीं। उन्होंने सभी को रंगपंचमी की शुभकामनाएँ और बधाई दी है।

एंबुलेंस को दिया रास्ता

इंदौर। गेर में इस बार इंदौरियत का असली रूप देखने को भी मिला। शनिवार दोपहर लगभग दो बजे एक एंबुलेंस गेर के बीच में फंस गई। इस पर पूरी जनता ने तुरंत रास्ता बनाया और एंबुलेंस को जगह दी।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी जयश्री जैन द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स 13, प्रेस कॉम्प्लेक्स ए.बी. रोड इंदौर से मुद्रित एवं 22, प्रेस काम्पलेक्स, प्रेस हाऊस, ए.बी. रोड इंदौर 452008 से प्रकाशित। प्रधान संपादक- डॉ. राजेश जैन, मो. 9425322301 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)